माडर्नाइजेशन और ज्यादा जनरेशन इन सारी चीजों को वाकायदा से देख रहे हैं । साथ ही साथ इतना भी मुझे कहना पड़ेगा कि सन् 1950 से 1987 के बीच

while the total sales of electricity have increased by 33 times, the sales to the agricultural sector have increased by 174 times.

यह अपनी पालिसी है कि कृषि के क्षेत्र में सस्ती से सस्ती, अच्छी से अच्छी बिजली हम लोग उनको दे सकें । सूखे के दौरान इसकी और ज्यादा जरूरत पड़ी है और उसमें हमने टारगेट से ज्यादा काम किया है, उसको पूरा किया है जैसे आर० इ० सी० के बारे में बताया गया है और इसके अलावा दोनों जगह इलैक्ट्रिफिकेशन और एनर्जाइजेशन में अपने लक्ष्य से ज्यादा काम किया है । घाटा तो बढ़ता ही जाता है पर साथ में और भी कारण हैं ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मैंने यह पूछा था कि 60 पैसे पर यूनिट एग्रीकल्चर को आप देते है तो क्या इसकी सब्सिडी आपको स्टेट गवर्नमेंट्स देती है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : बहुत अच्छा प्रश्न है । देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को पर कुछ एकाध ही दे रहे होंगे, सब नहीं दे रहे हैं पर उनको देना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि देश में गन्ना, गेहूं, चावल और जितनी भी पैदावार है उन सबकी एक कीमत केन्द्रीय सरकार देश भर में मुकर्रर करती है जबकि कुछ सूखे क्षेत्र मैं हैं, कुछ सिंचित हैं कैनाल्स से, कुछ सिंचित हैं बिजली के ट्यूबवेल्स से कुछ सिंचित हैं डीजल आयल से । सबके क्षेत्र अलग-अलग होते हुए भी एक कीमत मुकर्रर हो जाती है । आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया "जी नहीं" इसलिये चाहे डिफरेंस सोर्सेज है उत्पादन के तो फिर सारे देश में फसल की भांति एक ही कीमत या एक ही रेट मुकर्रर करने मे आपको क्या कठिनाई है ?

ऊर्जा और संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : क्योंकि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अलग-अलग राज्यों के है, उनके अलग अलग टैरिफ हैं । उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है । यह राज्यों का विषय है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Objections against Formation of National Power Grid

*461. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1977 given in the Rajya Sabha on the 14th March, 1988 and state:

(a) whether any objections were raised by any State Government against the formation of a National Power Grid; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) No objection was raised by any State Government against the formation of a National Power Grid during the Power Ministers' Conference held in February, 1988.

Waiting list for Maruti-800 cars

*465. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the total number of persons still waiting for the allotment of Maruti-800 ordinary car from the Maruti Udyog Limited, throughout the country;

(b) what is the annual production of ordinary Maruti-800 car;

(c) by what time the waiting list is likely to be cleared at the present rate of production;

(d) whether Government propose to allow some car manufacturers in the private sector to produce cars below 1000 cc in view of the popularity of small cars in the country especially in view of the fact that Maruti Udyog Limited is not in a position to meet the demand of the people; and

(e) if so, what are the details in this regard; and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) All 1983 car booking holders had been offered cars by June, 1987. Of the 1986 bookings, 1,13,864 customers were yet to be offered cars by end of February, 1988.

(b) The production of Maruti-800 standard cars in 1987-88 is anticipated to be about 51,000.

(c) The present waiting list is likely to be exhausted in approximately annother two years.

(d) and (e) The proposals received from four companies in private/State sector to manufacture cars below 1000 cc are under consideration, as a new and comprehensive automobile policy is being evolved by Government.

Incentives to 'no industry districts'

*467. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in spite of all the incentives given to N.I.Ds. (no industry districts), a sizeable number of them in the country have failed to attract even one medium or big industry;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government consider declaring them as a special category of N.I.D. and propose a better package of inncentives so as to give a start to the process of industrialisation of these backward districts?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (c) With effect from 1-4-83, No Industry Distrcts have been included in Category 'A' of re-classified backward areas and made eligible to highest rate of Central Investment subsidy, priority in grant of licences and other concessions.

Out of 93 districts identified as No Industry Districts, Industrial Licences/Registrations have been issued to 61 No Industry Districts for setting up industries there. Normally it takes 3-4 years for a project to fructify and their periods vary from project to project.

There is no proposal for additional special package of incentives to industries.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

*468. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के दौरान उस राज्य में इस प्रकार की और परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के कब तक स्थापित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा है ।